ग्रामीण विकास में नाबार्ड का बड़ा निवेश

ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिली बड़ी वित्तीय मदद

रु. 1.23 लाख करोड़ RIDF योजना से वितरित

नई दिल्ली, 4 अगस्त. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि नाबार्ड ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) में ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को लोन के रूप में रु. 1.59 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है.

मंत्री ने एक लिखित रु.जवाब में बताया कि इस राशि में से रु.1.23 लाख करोड़ रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से दिए गए, जबकि रु.36,439 करोड़ नाबार्ड की अन्य योजनाओं के तहत वितरित किए गए. इन योजनाओं में नाबार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड और फूड प्रोसेसिंग फंड जैसी कई प्रमुख योजनाएं शामिल हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड की यह वित्तीय सहायता ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता और बाजार तक पहुंच बेहतर होती है.

उन्होंने यह भी बताया कि नाबार्ड की पहल के कारण संस्थागत स्रोतों से लोन प्राप्त करने वाले कृषि परिवारों का अनुपात 2016-17 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 75 प्रतिशत हो गया है. इसके अलावा, नाबार्ड ने विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक 6,215 किसान उत्पादक संगठनों के गठन को बढ़ावा दिया है.

प्रत्यक्ष कर संग्रह में 13.48% उछाल

सरकार द्वारा कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती के बाद भी वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है. संसद में सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ?22,26,375 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.48 प्रतिशत अधिक है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि आकलन वर्ष 2020-21 से कॉर्पोरेट कर दरों में कमी के बाद से संग्रह में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है.

5 वर्षों में कर संग्रह दोगुना- पिछले पांच वर्षों में, भारत का कुल सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना से अधिक हो गया है. यह उच्च आर्थिक वृद्धि, बेहतर कर अनुपालन और नई डिजिटल तकनीक के उपयोग को दर्शाता है.

भारत बनेगा वैश्विक उत्पादन का अगुवा

मॉर्गन स्टेनली ने गिनाए भारत की मजबूती के आधार

नई दिल्ली, 4 अगस्त. भारत आने वाले दशकों में वैश्विक उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, जिसे मजबूत जनसंख्या वृद्धि, एक कार्यशील लोकतंत्र, वृहद स्थिरता-केंद्रित नीतियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यमी वर्ग और सामाजिक परिणामों जैसे मजबूत आधारभूत कारकों का समर्थन प्राप्त है.

यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई. मॉर्गन स्टेनली रिसर्च द्वारा संकलित आंकड़ों में कहा गया है कि ये मजबूत कारक भारत को दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उपभोक्ता बाजारों में से एक बना देंगे, एक बड़े ऊर्जा परिवर्तन को गति देंगे, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ावा देंगे और सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले ऋण के अनुपात को बढ़ाएंगे

सकल घरेलू उत्पाद में तेल की गहनता में कमी

बढ़ते निर्यात - विशेष रूप से सेवाओं - और राजकोषीय समेकन से बचत असंतुलन कम होने और वास्तविक ब्याज दरों को संरचनात्मक रूप से कम रखने की उम्मीद है. मॉर्गन स्टेनली ने आगे कहा कि आपूर्ति पक्ष में सुधार और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण द्वारा समर्थित कम मुद्रास्फीति अस्थिरता, ब्याज दरों और विकास में उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद करेगी. उच्च वृद्धि, कम अस्थिरता और गिरती ब्याज दरों का यह संयोजन उच्च बाजार मूल्यांकन को बढ़ावा देता है और परिवारों को अपनी बचत का अधिक हिस्सा इक्विटी में लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है. हालांकि निकट भविष्य में मार्केट रिटर्न ग्रोथ साइकिल में विश्वास पर निर्भर करेगा, ब्रोकरेज अपने आउटलुक में आम सहमति से आगे बना हुआ है.

चाय उत्पादन में 9% की गिरावट

मौसम और कीटों ने बढ़ाई मुश्किलें

कोलकाता, 4 अगस्त. भारत में चाय उत्पादन में इस साल जून में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो 14.67 करोड़ किलोग्राम (2024) से घटकर 13.35 करोड़ किलोग्राम रह गया. भारतीय चाय संघ ने इस कमी का कारण प्रतिकूल मौसम और कीटों के हमले को बताया है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों, जैसे पश्चिम बंगाल और असम, में उत्पादन जून 2025 में 12.15 करोड़ किलोग्राम से घटकर 11.25 करोड़ किलोग्राम हो गया. दक्षिण भारत में भी उत्पादन में कमी देखी गई, जहां यह 2.52 करोड़ किलोग्राम (2024) से घटकर 2.09 करोड़ किलोग्राम रह गया.

बड़े और संगठित बागान मालिकों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ, जो जून 2024 में 6.83 करोड़ किलोग्राम था, वह इस साल 5.52 करोड़ किलोग्राम तक सिमट गया. छोटे उत्पादकों का योगदान भी 7.83 करोड़ किलोग्राम से घटकर 6.82 करोड़ किलोग्राम हो गया.

किस्मों के हिसाब से, 'सीटीसी' (क्रश, टियर, कर्ल) चाय का उत्पादन 11.78 करोड़ किलोग्राम रहा.

सेंसेक्स 0.52 प्रतिशत, निफ्टी 0.64 प्रतिशत लाभ

मुंबई, 04 अगस्त (वार्ता) वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों ने सप्ताह के पहले दिन सोमवार को मजबूती दिखायी और बीएसई का 30 प्रमुख शेयरों वाला सेंसेक्स 418.81 अंक यानी 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,018.72 अंक और एनएसई का निफ्टी-50 भी 157.40 अंक सुधरकर 24,722.75 अंक पर बंद हुआ. स्थानीय बाजारों में धातु, वाहन, मीडिया, निर्माण और आईटी कंपनियों के शेयरों में निवेशकों का विश्वास बढ़ा हुआ था जबकि बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में मिला-जुला रुख दिखा. बीएसई के 30 में से 26 शेयर लाभ और चार हानि में बंद हुए. लाभ में रहे प्रमुख शेयरों में टाटा मोटर्स में 4.31 प्रतिशत, बीईएल में 3.55 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स में 3.24 प्रतिशत और टेक महिंद्रा में 2.53 प्रतिशत की अच्छी तेजी दर्ज की गयी.

ग्लोबल पेट्रोकेमिकल में भारत की दावेदारी

बीसीजी रिपोर्ट में भारत की रणनीतिक भूमिका

घरेलू मांग और उत्पादन क्षमता बनी ताकत

नई दिल्ली, 4 अगस्त. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती विनिर्माण क्षमता के कारण पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कंसोलिडेटर के रूप में उभरने के लिए तैयार है.

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की %प्रीपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ पेट्रोकेमिकल कंसोलिडेशन% शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कम मार्जिन और अत्यधिक क्षमता के कारण यह क्षेत्र एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक पेट्रोकेमिकल कंपनियों को कम मार्जिन का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें औसत आरओसीई 2019 के 8% से घटकर 2024 में लगभग 4% रह गया है. इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, कई क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि मांग वृद्धि से आगे निकल रही है, जिससे कंसोलिडेशन और रेशनलाइजेशन की आवश्यकता बढ़ गई है. बीसीजी के प्रबंध निदेशक कौस्तुभ वर्मा ने कहा, वैश्विक पेट्रोकेमिकल परिदृश्य कंसोलिडेशन के एक नए चरण की ओर बढ़ रहा है और भारत एक रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है. मजबूत घरेलू मांग और बढ़ते विनिर्माण आधार के साथ, भारतीय कंपनियों के पास लक्षित मर्जर और एक्विजिशन और टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं में निवेश करके क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित करने का शानदार अवसर है.

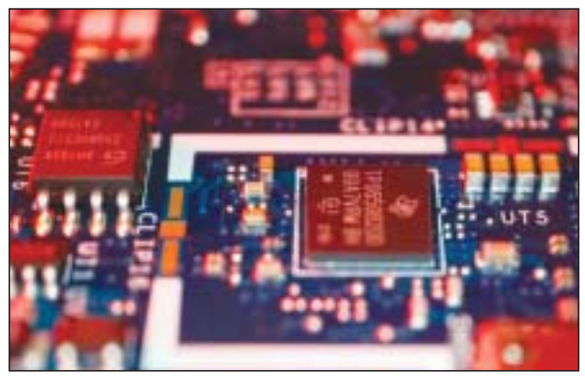

2030 तक भारत बनेगा चिप हब

9.6 लाख करोड़ का होगा सेमीकंडक्टर बाज़ार | **2023** में 38 बिलियन था सेमीकंडक्टर बाजार

नई दिल्ली, 4 अगस्त, भारत का सेमीकंडक्टर बाज़ार 2030 तक दोगुना से अधिक बढ़कर 9.6 लाख करोड़ रुपये (.100-110 बिलियन) तक पहुँचने की उम्मीद है. उद्योग के अनुमानों के अनुसार, 2023 में यह बाज़ार लगभग .38 बिलियन का था, जो 2024-2025 में बढ़कर .45-50 बिलियन हो गया.

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण की तीन प्रमुख श्रृंखलाओं—उपकरण, सामग्री और सेवाएँ, और अनुसंधान एवं विकास (ऋ×ष्ठ)—में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरने की क्षमता रखता है. बयान में कोविड महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में आई समस्याओं का हवाला देते हुए भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया.

वर्तमान में, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का सेमीकंडक्टर उद्योग पर दबदबा है. केवल ताइवान ही दुनिया के 60त्न से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है. इस पर निर्भरता ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम में डाल दिया है, जिसे देखते हुए कई देश अब सुरक्षित और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएँ बना रहे हैं.

इस मिशन के तहत, माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर और अन्य सहित कई कंपनियों ने भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए कुल ?1.55 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. इसके अलावा, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, सेमीकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण 2 से 4 सितंबर, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करेगा.

अमेरिकी शुल्क से भारत पर असर : मूडीज

नई दिल्ली, 4 अगस्त. रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी बाजार तक सीमित पहुंच होने से भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएं कम होंगी. एजेंसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है. यह शुल्क 7 अगस्त से लागू होगा.

मूडीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रिश्चियन डी गुजमैन ने बताया कि भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया यह संशोधित शुल्क एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य प्रमुख निर्यातकों की तुलना में काफी अधिक है, जिनकी शुल्क दरें 15 से 20 प्रतिशत के बीच हैं. गुजमैन ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक सीमित पहुंच से भारत के विनिर्माण क्षेत्र, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रों, के लिए बढ़ने की संभावना कम होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका 2024 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 18 प्रतिशत हिस्सा था.

मूडीज ने उम्मीद जताई कि इन बाहरी दबावों के बावजूद भारत की घरेलू मांग मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विदेश व्यापार पर कम निर्भर है.

मॉयल ने वित्त वर्ष 26 में किया रिकॉर्ड जुलाई उत्पादन

नई दिल्ली, 4 अगस्त. मॉयल ने जुलाई 2025 में 1.45 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 11.4त्न की प्रभावशाली वृद्धि है. कंपनी ने यह उपलब्धि प्रतिकूल मौसम के बावजूद हासिल की. भारी बारिश के बावजूद, मॉयल ने अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान मजबूत परिचालन प्रदर्शन दिखाया है. इस अवधि में उत्पादन 6.47 लाख टन बिक्री 5.01 लाख टन और 43,215 मीटर की अन्वेषण ड्रिलिंग की गई है.

एयरटेल ने अपना एआई रेडी क्लाउड किया लॉन्च

नयी दिल्ली, 04 अगस्त (वार्ता) एयरटेल ने भविष्य में अपने कारोबार और सेवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए सोमवार को एयरटेल क्लाउड लॉन्च करने की घोषणा की.

एयरटेल के प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल ने एयरटेल क्लाउड के लॉन्च की घोषणा करते हुए कहा कि इसका डेटा सेंटर दिल्ली और चेन्नई में स्थित होगा जिसे एयरटेल का नेक्स्ट्रा होस्ट करेगा. यह खास रूप से दूरसंचार कंपनी के अनुरूप होगा. उन्होंने बताया कि इससे ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा में काफी सुधार होगा. इसका असर अगले 10 साल में काफी देखने को मिलेगा और ग्राहकों की संख्या काफी बढ़ जायेगी.

उन्होंने बताया कि एयरटेल क्लाउड के स्टोरेज क्षमता 250 पेंटाबाइट होगी. इसके लिए कंपनी ने सिंगापुर में सिंगटेल, अफ्रीका में एयरटेल अफ्रीका और ग्लोबल टेलीकॉम के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं.

समाचार विशेष

ब्रजेश पाठक से मुलाकात, माया की तारीफ...

क्या अखिलेश के लिए पश्चिम की राह मुश्किल बना रहे राकेश टिकैत?

लखनऊ. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की सक्रियता से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. राकेश टिकैत ने हाल ही में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की. फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की तारीफ करते हुए उन्होंने 'नंबर वन मुख्यमंत्री' बता दिया.

राकेश टिकैत की डिप्टी सीएम से मुलाकात और मायावती को लेकर दिए बयान ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत का झुकाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है, लेकिन अब उनकी यह नई रणनीति सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती है. राकेश टिकैत का प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा ख़ासा है. इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला. 2022 में राकेश टिकैत ने सपा-रालोद गठबंधन का समर्थन किया था, जिसका परिणाम भी देखने को मिला था.

हाल ही में 29 जुलाई को राकेश टिकैत ने लखनऊ में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. इस मुलाकात को शुरुआत में शिष्टाचार भेंट माना गया, लेकिन टिकैत के सुल्तानपुर पहुंचने पर उनके तेवर बदल गए. उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती को उत्तर प्रदेश का 'सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री' करार देते हुए उनकी सरकार की किसान नीतियों की जमकर तारीफ की.

पश्चिमी यूपी में टिकैत का प्रभाव

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत का किसानों के बीच मजबूत प्रभाव रहा है. 2020-21 के किसान आंदोलन ने उन्हें इस क्षेत्र में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया. 2022 के विधानसभा चुनावों में टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ किसानों से वोट न देने की अपील की थी, जिसका असर पश्चिमी यूपी में सपा-आरएलडी गठबंधन की जीत के रूप में देखा गया. 2024 के लोकसभा चुनावों में भी सपा को गैर-जाटव दलित और गैर-यादव पिछड़े वर्गों में टिकैत के समर्थन का लाभ मिला.

विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की यात्रा

तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी होंगे शामिल, बैठक में बनी रणनीति

पटना. बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन राज्यभर में जनसंवाद यात्रा निकालने जा रहा है. इस यात्रा का उद्देश्य जनता तक पहुंचकर एनडीए सरकार की नाकामियों को उजागर करना और विपक्षी एकता का प्रदर्शन करना है.

इस निर्णय की घोषणा बुधवार को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई समन्वय समिति की बैठक के बाद की गई. तीन घंटे चली इस बैठक में महागठबंधन के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया.

यात्रा रक्षाबंधन के बाद होगी शुरू

तेजस्वी यादव ने मीडिया को जानकारी दी कि यह यात्रा रक्षाबंधन के बाद शुरू की जाएगी. यात्रा हर प्रमंडल में निकाली जाएगी और बूथ स्तर तक जनता से सीधा संवाद किया जाएगा. तेजस्वी ने बताया कि यात्रा के जरिए जनता को बिहार में कथित 70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और वोटर लिस्ट से नाम हटाने जैसे मुद्दों के बारे में बताया जाएगा.

शशि थरूर की आम पार्टी की कूटनीति

थरूर विदेशी संपर्कों को पुनर्जीवित कर दिखा रहे अपना प्रभाव

तिरूवनंतपुरम. कांग्रेस के तिरूवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर वैसे तो हर साल आम की पार्टी देते हैं. लेकिन इस बार की पार्टी कुछ खास थी. इस बार की पार्टी में राजनीति से ज्यादा कूटनीति दिखी. तभी ऐसा लगा कि थरूर अपनी पोजिशनिंग में लगे हैं.

आमतौर पर उनकी पार्टी में सभी राजनीतिक दलों के नेता बुलाए जाते हैं. लेकिन इस बार उनकी पार्टी में बड़ी संख्या में राजनयिक आमंत्रित थे. दुनिया भर के देशों के दूतावासों के अधिकारियों और कर्मचारियों को थरूर ने बुलाया था और वे आए भी थे. कहा जा रहा है कि थरूर जब से पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को बताने गए भारत के एक डेलिगेशन का नेतृत्व करके लौटे हैं तब से वे अपने विदेशी संपर्कों को पुनर्जीवित कर रहे हैं.

ध्यान रहे डेलिगेशन लौटने के बाद भी वे कई देशों में गए, जहां भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उनका स्वागत हुआ और उन्होंने भारत की बात रखी. माना जा रहा है कि आम की पार्टी में विदेशी मेहमानों और राजनयिकों को बुला कर थरूर ने दिखाया है कि वे एक प्रभावी विदेश मंत्री हो सकते हैं. हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनके भाजपा में जाने और विदेश मंत्री बनने की चर्चा थम गई है. बहरहाल, थरूर की आम पार्टी की राजनीति की बात करें तो वहां उनके लिए बहुत संभावना नहीं दिखी. कांग्रेस को थोड़े से नेता जरूर पहुंचे, लेकिन वे सभी केरल के थे और उनका भी मकसद यह पता लगाना था कि पार्टी में क्या हो रहा है और कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का उपस्थिति देख कर तो लगा कि वहां अब थरूर अलग थलग हो गए हैं.

विशेष | **जिला पंचायत के चुनाव में परिवारवाद का खामियाजा भुगतना पड़ा**

भाजपा तो जीत गई, लेकिन परिवार हार गए

देहरादून. उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तो जीत गई, लेकिन परिवार हार गए. पार्टी ने जहां भी दिग्गजों के परिजन को मैदान में उतारा, वहीं जनता ने उन्हें नकार दिया. पंचायत चुनाव में पार्टी दिग्गजों के बहू, बेटे, पत्नी को मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया.

नैनीताल में भाजपा विधायक सरिता आर्या के बेटे रोहित आर्या, सल्ट विधायक महेश जीना के बेटे करन को स्याल्दे बबलिया क्षेत्र पंचायत सीट, बदरीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी, लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की बेटी, लैंसडोन विधायक दिलीप रावत की पत्नी, नैनीताल जिला में भाजपा की निर्वतमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू, चमोली भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल भर्तवाल जैसे तमाम दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा.

तो चुनाव नतीजों की तस्वीर कुछ और होती

भाजपा चुनाव में कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर सियासी प्रहार करती रही. मतदाताओं ने कांग्रेस के परिवारवाद को स्वीकार किया, जबकि भाजपा को नकारा है.

राजनीतिक दिग्गजों का मानना है कि भाजपा ने समर्थन देने में अगर परिवारवाद के बजाय मजबूत दावेदारों का चयन किया होता तो चुनाव नतीजों की तस्वीर कुछ और ही सामने होती.

धामी सरकार की ऐतिहासिक जीत

पंचायत चुनाव की यह जीत न केवल उत्साहवर्धक है बल्कि ऐतिहासिक भी है. भाजपा को 2019 में 200 सीटें मिली थीं. उसमें हरिद्वार भी शामिल था. अब भाजपा को हरिद्वार छोड़कर 216 सीटें मिली हैं. उस लिहाज से हरिद्वार की 44 सीटों को जोड़कर यह आंकड़ा 260 है. यह अब तक सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की पंचायतों में ऐतिहासिक जीत है. सभी जिलों में भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है.

-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा